

प्रथम-मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

राष्ट्रवाद एवं विकास

गुणात्मक, रूचिकर एवं क्रियात्मक
अध्ययन मार्गदर्शिका

(राजनीति-विज्ञान प्रवक्ताओं हेतु)

2016-17



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

प्रथम-मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

राष्ट्रवाद एवं विकास

मुख्य सलाहकार

आई.ए.एस. शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार

चेयरपर्सन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली

मार्ग दर्शन

श्रीमती अनिता सेतिया

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

डॉ. प्रतिभा शर्मा

संयुक्त निदेशक एवं राज्य शिक्षक समन्वयक एस.सी.ई.आर.टी.

शैक्षिक समन्वयक

डॉ. नीलम

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट केशव कुमार

लेखन समूह

डाइट राजेन्द्र नगर

डाइट केशव पुरम

सी.बी.एस.ई. विषय विशेषज्ञ

शिक्षा निदेशालय

शिक्षा निदेशालय

शिक्षा निदेशालय

रावल कॉलेज ऑफ एजुकेशन

शिक्षा निदेशालय

शिक्षा निदेशालय

एस.सी.ई.आर.टी.

एस.सी.ई.आर.टी.

डॉ. नीलम

डॉ. पवन कुमार

श्रीमान मदन साहनी

डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी

श्रीमान श्याम किशोर गुप्ता

श्रीमान तपराज दत्त

श्रीमान रमेश

मोहम्मद नासिर

श्रीमती ऊषा किरन

श्रीमान अरुण कुमार

श्रीमान राजीव रंजन

वेटिड एवं सम्पादन

श्रीमान मदन साहनी

डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी

प्रकाशन प्रभारी

सपना यादव

प्रकाशन समूह

श्री नवीन कुमार, राधा एवं जय भगवान

प्रकाशक : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

टंकण : एजुकेशनल स्टोर्स, एस-5, बुलन्दशहर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, साईट-1, गाजियाबाद (उ.प्र.)

विषय-सूची

1. राष्ट्रवाद	40
2. राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ	47
3. विकास (DEVELOPMENT)	55
4. नियोजित विकास की राजनीति	61
5. सामाजिक न्याय	67
6. जन आन्दोलनों का उदय	75
7. पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	82

आमुख-1

21 वीं सदी में सरकार का मुख्य ध्यान आम आदमी को सशक्त करते हुए जीवन के बुनियादी कौशलों को विकसित करना है ताकि भारत के लोकतंत्र को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र भविष्य के आने वाले नागरिक हैं अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे न केवल अच्छे अंक प्राप्त करें बल्कि वे जिम्मेदार व उत्पादित नागरिक बन सकें।

प्रस्तुत सहायक पाठ्य सामग्री शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ताओं हेतु और तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का विस्तार करना है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद तथा मण्डलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समय-समय पर तैयार की गयी शिक्षक संदर्शिकाएं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रयास है। इन शिक्षक संदर्शिका का उद्देश्य शिक्षण अधिगम को अधिक अंतः क्रियात्मक बनाना है जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा 2005 में रेखांकित है।

मैं इन विषय विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। साथ ही मैं संदर्शिका लेखन में सम्मिलित संयोजकों, लेखक समूह व संपादन मंडल के साथ-साथ सभी राज्य शैक्षिक व अनुसंधान परिषद तथा मंडलीय शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदाधिकारियों व प्रकाशन विभाग के अमूल्य योगदान की सराहना करती हूँ।

यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत संदर्शिका अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित हैं।

—अनिता सेतिया

निदेशक

आमुख-2

प्रस्तुत सहायक पाठ्यसामग्री को राजनीति-विज्ञान की अवधारणा के अनुसार संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। कक्षा ग्यारहवीं और बाहरवीं के विभिन्न संबंधित अध्यायों को इस माड्यूल में मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों कक्षाओं की राजनीति विज्ञान की सामग्री को 6 माड्यूल के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया गया है:-

1. प्रथम माड्यूल → राष्ट्रवाद एवं विकास
2. द्वितीय माड्यूल → संविधान का दर्शन एवं व्यवहार
3. तृतीय माड्यूल → राजनीतिक सिद्धांत व अवधारणाएँ

4. चतुर्थ माड्यूल → समकालीन विश्व संगठन एवं भारत
5. पंचम माड्यूल → भारतीय शासन एवं राजनीति
6. षष्ठम् माड्यूल → शीतयुद्धोत्तर विश्व राजनीति

उपरोक्त माड्यूल के अंतर्गत अवधारणाओं को इस रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिससे एक समझ बने न कि अवधारणाएँ केवल ज्ञान, तथ्यों एवं सूचनाओं तक ही सीमित रह जाएं। साथ ही प्रत्येक प्रकरण में अभ्यास व क्रियाकलापों को रोचक बनाते हुए इस तरह संरचित किए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत संवर्धित मूल्यों की भी बात की गयी है जो कि संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं।

माड्यूल निर्माण में जो समूह कार्य के लिए बनाया गया उन्हें लंबा शिक्षण अनुभव है।

माड्यूल निर्माण समिति के सदस्यों की शैक्षिक विशेषज्ञता और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य समय और इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ/करता हूँ।

—डॉ. नीलम

डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

डाइट केशव पुरम्

POLITICAL SCIENCE (028)

Class - XI (2016-17)

Units		Periods: 220	Marks: 100
Part A: Indian Constitution at work			
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights in the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	The Executive	11	
5	The Legislature	11	10
6	The Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a living document	11	8
	Total	110	50
Part B: Political Theory			
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	11	10
19	Development	11	
	Total	110	50

COURSE CONTENT

Part A: Indian Constitution at Work

1. Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution (17 Periods)

Constitution: Why and How, The making of the Constitution, the Constituent Assembly, Procedural achievements and Philosophy of the Constitution.

2. Rights in the Indian Constitution (16 Periods)

The importance of Rights, Fundamental Rights in the Indian Constitution, Directive Principles of State Policy, Relationship between Fundamental Rights and Directive Principles

3. Election and Representation (11 Periods)

Elections and Democracy, Election System in India, Reservation of Constituencies, Free and Fair Elections, Electoral Reforms

4. Legislature (11 Periods)

Why do we need a Parliament? Two Houses of Parliament. Functions and Power of the Parliament, Legislative functions, control over Executive. Parliamentary committees. Self-regulation.

5. Executive **(11 Periods)**

What is an Executive? Different Types of Executive. Parliamentary Executive in India, Prime Minister and Council of Ministers. Permanent Executive: Bureaucracy.

6. Judiciary **(11 Periods)**

Why do we need an Independent Judiciary? Structure of the Judiciary, Judicial Activism, Judiciary and Rights, Judiciary and Parliament.

7. Federalism **(11 Periods)**

What is Federalism? Federalism in the Indian Constitution, Federalism with a strong Central Government, conflicts in India's federal system, Special Provisions.

8. Local Governments **(11 Periods)**

Why do we need Local Governments? Growth of Local Government in India, 73rd and 74th Amendments, implementation of 73rd and 74th Amendments.

9. Constitution as a Living Document **(11 Periods)**

Are Constitutions static? The procedure to amend the Constitution. Why have there been so many amendments? Basic Structure and Evolution of the Constitution. Constitution as a Living Document.

Part B: Political Theory

10. Political Theory: An Introduction (10 Periods)

What is Politics? What do we study in Political Theory? Putting Political Theory to practice. Why should we study Political Theory?

11. Freedom **(11 Periods)**

The Ideal of Freedom. What is Freedom? Why do we need constraints? Harm principle. Negative and Positive Liberty.

12. Equality **(11 Periods)**

Significance of Equality. What is Equality? Various dimensions of Equality. How can we promote Equality?

13. Social Justice (12 Periods)

What is Justice? Just Distribution. Justice as fairness. Pursuing Social Justice.

14. Rights **(11 Periods)**

What are Rights? Where do Rights come from? Legal Rights and the State. Kinds of Rights. Rights and Responsibilities.

15. Citizenship **(11 Periods)**

What is citizenship? Citizen and Nation, Universal Citizenship, Global Citizenship

16. Nationalism **(11 Periods)**

Nations and Nationalism, National Self-determination, Nationalism and Pluralism

17. Secularism (11 Periods)

What is Secularism? What is Secular State? The Western and the Indian approaches to Secularism. Criticisms and Rationale of Indian Secularism.

18. Peace (11 Periods)

What is Peace? Can violence ever promote peace? Peace and the State. Different Approaches to the pursuit of peace. Contemporary challenges to peace.

19. Development (11 Periods)

What is development? Dominant, development Model and alternative conceptions of development.

Prescribed Books:

1. Indian Constitution at work, Class XI, Published by NCERT
2. Political Theory, Class XI, Published by NCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17										
POLITICAL SCIENCE			Code No. 028			CLASS-XII				
Time: 3 Hours						Max. Marks: 100				
S. No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages	Map Question Picture based interpretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks	% weightage
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific-facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)			1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)	<ul style="list-style-type: none"> Reasoning Analytical Skills Critical thinking 	1	1		1	1	2	25	25%
4	High Order Thinking Skills (Analysis fit Synthesis-Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety of sources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation - (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
	Total		1×5=5	2×5=10	4×6=24	5×3=15	5×2=10	6×6=36	100	100%

POLITICAL SCIENCE (Code No. 028)

Class -XI (2016-17)

Question Paper Design

Units		Periods	Marks
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights of the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	Executive	11	
5	Legislature	11	10
6	Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a Living Document	11	08
	Total	110	50
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	11	10
19	Development	11	
	Total	110	50

3. Weightage of Difficulty Level Percentage

Estimated difficulty level 20%

Difficult 50%

Average Easy 30%

4. Scheme of Options:

There is internal choice for long answer questions of 6 marks.

There are three passage - based questions of 5 marks each. No questions from plus (+) boxes.

5. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

POLITICAL SCIENCE (Code No. 028)

Class -XII (2016-17)

Units		Periods	Marks
Part A: Contemporary World Politics			
1	Cold War Era	14	14
2	The End of bipolarity	13	
3	US Hegemony in World Politics	13	
4	Alternative centres of Power	11	16
5	Contemporary South Asia	13	
6	International Organizations	13	10
7	Security in Contemporary World	11	
8	Environment and Natural Resources	11	10
9	Globalisation	11	
	Total	110	50
Part B: Politics in India since Independence			
10	Challenges of Nation-Building	13	
11	Era of One-party Dominance	12	16
12	Politics of Planned Development	11	
13	India's External relations	13	6
14	Challenges to the Congress System	13	12
15	Crisis of the Democratic Order	13	
16	Rise of Popular Movements	11	
17	Regional aspirations	11	16
18	Recent Developments in Indian Politics	13	
	Total	110	50

COURSE CONTENTS

Part A: Contemporary World Politics

1	Cold War Era Emergence of two power blocs after the second world war. Arenas of the cold war. Challenges to Bipolarity: Non Aligned Movement, quest for new international economic order. India and the cold war.	14 Periods
2	The End of Bipolarity New entities in world politics: Russia, Balkan states and Central Asian states, Introduction of democratic politics and capitalism in post-communist regimes. India's relations with Russia and other post-communist countries.	13 Periods
3	US Hegemony in World Politics % Growth of unilateralism: Afghanistan, first Gulf War, response to 9/11 and attack on Iraq. Dominance and challenge to the US in economy and ideology. India's renegotiation of its relationship with the USA	13 Periods
4	Alternative Centres of Power Rise of China as an economic power in post-Mao era, creation and expansion of European Union, ASEAN. India's changing relations with China.	11 Periods
5	Contemporary South Asia in the Post-Cold War Era Democratisation in Pakistan and Nepal. Ethnic conflict in Sri Lanka, Impact of economic globalization on the region. Conflicts and efforts for peace in South Asia. India's relations with its neighbours.	13 Periods
6	International Organizations Restructuring and the future of the UN. India's position in the restructured UN. Rise of new international actors: new international economic organisations, NGOs. How democratic and accountable are the new institutions of global governance?	13 Periods
7	Security in Contemporary World Traditional concerns of security and politics of disarmament. Non-traditional or human Security: global poverty, health and education. Issues of human rights and migration.	11 Periods
8	Environment and Natural Resources Environment movement and evolution of global environmental norms. Conflicts over traditional and common property resources. Rights of indigenous people. India's stand in global environmental debates.	11 Periods
9	Globalisation Economic, cultural and political manifestations. Debates on the nature of consequences of globalisation. Anti-globalisation movements. India as an arena of globalization and struggle against it.	11 Periods
Part B: Politics in India since Independence		
10	Challenges of Nation-Building Nehru's approach to nation-building; Legacy of partition: challenge of refugee resettlement, the Kashmir problem. Organisation and reorganization of states; Political conflicts over language.	13 Periods
11	Era of One-Party Dominance First three general elections, nature of Congress dominance at the national level, uneven dominance at the state level, coalitional nature of Congress. Major opposition parties.	12 Periods
12	Politics of Planned Development Five year plans, expansion of state sector and the rise of new economic interests. Famine and suspension of five year plans. Green revolution and its political fallouts.	11 Periods
13	India's External Relations Nehru's foreign policy. Sino-Indian war of 1962, Indo-Pak war of 1965 and 1971. India's nuclear programme. Shifting alliance in world politics.	13 Periods
14	Challenges to the Congress System Political succession after Nehru. Non-Congressism and electoral upset of 1967, Congress split and reconstitution, Congress' victory in 1971 elections, politics of 'garibi hatao'.	13 Periods

15	Crisis of the Democratic Order Search for 'committed' bureaucracy and judiciary. Navnirman movement in Gujarat and the Bihar movement. Emergency: context, constitutional and extra-constitutional dimensions, resistance to emergency. 1977 elections and the formation of Janata Party. Rise of civil liberties organisations.	13 Periods
16	Popular Movements in India Farmers' movements, Women's movement, Environment and Development-affected people's movements. Implementation of Mandal Commission report and its aftermath.	11 Periods
17	Regional Aspirations Rise of regional parties. Punjab crisis and the anti Sikh riots of 1984. The Kashmir situation. Challenges and responses in the North East.	11 Periods
18	Recent Developments in Indian politics Participatory upsurge in 1990s. Rise of the JD and the BJP. Increasing role of regional parties and coalition politics. Coalition governments: NDA (1998 - 2004) UPA (2004 - 2014) NDA (2014 onwards)	13 Periods

Prescribed Books:

1. Contemporary World Politics, Class XII, Published by NCERT
2. Politics in India since Independence, Class XII, Published by NCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

COURSE CONTENTS

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17										
Code No. 028										
POLITICAL SCIENCE						CLASS-XII				
Time: 3 Hours						Max. Marks: 100				
S.No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages and Picturres	Map Question Picture based interpretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks age	%weight
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)	• Reasoning • Analytical Skills • Critical thinking		1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)		1	1		1	1	2	25	25%
4	High Order Thinking Skills (Analysis & Synthesis- Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety ofsources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation- (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
Total			1×5=5	2×5=10	4×6=24	5×3=15	5×2=10	6×6=36	100	100%

Note: Care is to be taken to cover all chapters.

The weightage or the distribution of marks over the different dimensions paper shall be as follows:-

1.Weightage of Content

Part A: Contemporary World Politics

Units		Marks
1	Cold War Era	14
2	The End of Bipolarity	
3	US Hegemony in World Politics	
4	Alternative Centres of Power	16
5	Contemporary South Asia	
6	International Organizations	10
7	Security in Contemporary World	
8	Environment and Natural Resources	,0
9	Globalization	
	Total	50

Part B: Politics in India since Independence

Units		Marks
10	Challenges of Nation-Building	
11	Era of One-Party Dominance	16
12	Politics of Planned Development	
13	India's External Relations	6
14	Challenges to the Congress System	12
15	Crisis of the Democratic Order	
16	Rise of Popular Movements	
17	Regional Aspirations	16
18	Recent Developments in Indian Politics	
	Total	50

3. Weightage of Difficulty Level Percentage

Estimated difficulty level 20%

Difficult 50%

Average Easy 30%

4. Scheme of Options:

There is internal choice for long answer questions of 6 marks.

There are three passage - based questions of 5 marks each. No questions from plus (+) boxes.

5. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI

Time : 3 Hrs.]

[M. M. : 100

General Instructions :

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Questions 1 to 5 are of one mark each. The answer to these questions should not exceed 20 words each.
- (iii) Questions 6 to 10 are of two marks each. The answer to these questions should not exceed 40 words each.
- (iv) Questions 11 to 16 are of four marks each. The answer to these questions should not exceed 100 words each.
- (v) Questions 17 to 19 are passage based. These are of 5 marks each.
- (vi) Questions 20 to 21 are map or picture based. These questions too are of 5 marks each.
- (vii) Questions 22 to 27 are of six marks each. The answer to these questions should not exceed 150 words each.

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सभी प्रश्न एक-एक अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (iii) प्रश्न संख्या 6 से 10 तक सभी प्रश्न दो-दो अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (iv) प्रश्न संख्या 11 से 16 तक सभी प्रश्न चार-चार अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (v) प्रश्न संख्या 17 से 19 गद्यांशों पर आधारित हैं। इनके पाँच-पाँच अंक हैं।
- (vi) प्रश्न संख्या 20 से 21 मानचित्र अथवा चित्रों पर आधारित हैं। इनके अंक भी पाँच-पाँच हैं।
- (vii) प्रश्न संख्या 22 से 27 दीर्घ उत्तरीय हैं। सभी प्रश्न छः-छः अंकों के हैं। इनके उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. What is meant by Mandamus ?
मैंडामस शब्द का क्या अर्थ है ? 1
2. From which country we borrowed the power of Judicial Review ?
भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की धारणा कहाँ से ली गई है ? 1
3. What is meant by peace.
शान्ति से क्या तात्पर्य है ? 1
4. Write two political rights of a citizen ?
नागरिक के दो राजनीतिक अधिकार लिखिए। ½) 1
5. Write full form of UNDP.
UNDP का पूर्ण रूप लिखिए। 1
6. What do you understand by 'Question Hour' ?
'प्रश्न काल' से आप क्या समझते हैं ? 2
7. Explain any two jurisdictions of Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए। 2
8. Mention two features of Indian Federation.
भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएँ लिखिए। 2
9. "Indian Constitution is a living document." Justify by writing your opinion about the statement.
"भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है।" अपना तर्क देते हुए इस वाक्य का औचित्य स्पष्ट कीजिए। 2
10. Distinguish between natural rights and fundamental rights.
प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में प्रमुख अंतर बताइए। 2
11. Describe any four functions of Election Commission of India.
भारतीय निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। 4
12. What are the demands raised by states in their quest for greater autonomy ?
ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या माँगें उठाई हैं ? 4
13. Write any four changes that have been made in the Panchayati Raj System under 73rd Constitutional Amendment.
73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज प्रणाली में किए गए कोई चार परिवर्तन लिखिए। 4

14. What does it mean to give each person his/her due ? How has the meaning of 'giving each his due' changed with time ? 4

हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है ? हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला जा सकता है ?

15. Mention four differences between State and Nation. 4

राज्य और राष्ट्र में चार अन्तर बताइए।

16. 'Disarmament is necessary.' Why ? 4

'निःशस्त्रीकरण आवश्यक है।' क्यों ?

17. Read the following passage and answer the questions based on it :

A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognise these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizens in Constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the 'Bill of rights'. A bill of rights prohibits government from thus acting against the rights of individuals and ensure a remedy in case there is violation of these rights.

From whom does a Constitution protect the rights of the individual ? The rights of a person may be threatened by another person or private organisation. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So, it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government (the legislature, executive, bureaucracy or even the judiciary) in the course of their functioning, may violate the rights of the person.

- (a) How many fundamental rights are given to Indian citizen in the Constitution of India ? 1

- (b) In case of violation of the fundamental rights of an individual, which fundamental right ensures remedy ? 1

- (c) From whom does the Constitution protect the rights of an individual ? 3

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

प्रजातंत्र में सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा-पत्र' कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा-पत्र

सरकार को नागरिकों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है।

संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग (विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका) अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

- (a) भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
- (b) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में किस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत उनकी रक्षा की गई है?
- (c) नागरिक के अधिकारों को किससे संरक्षित किया गया है?

18. Read the following passage and answer the questions :

Positive liberty recognises that one can be free only in society (not outside it) and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society, outside this area, as such. Of course, negative liberty would like to expand this minimum area as much as is possible keeping in mind, however, the stability of society. Generally they both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by invoking arguments of positive liberty.

- (a) What is meant by positive liberty? 2
- (b) What is the concept of negative liberty? 2
- (c) According to the passage what negative statement are given against positive liberty? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

सकारात्मक स्वतन्त्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतन्त्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं और इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतन्त्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतन्त्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालाँकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व के ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतन्त्रताएँ साथ-साथ चलती हैं और एक-दूसरे का समर्थन करती हैं लेकिन ऐसा भी

हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे।

- (a) सकारात्मक स्वतन्त्रता से क्या अभिप्राय है?
- (b) नकारात्मक स्वतन्त्रता की अवधारणा क्या है?
- (c) गद्यांश के अनुसार, सकारात्मक स्वतन्त्रता के विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है?

19. Read the following passage and answer the questions based on it :

Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to an end. Since many of these systems have a sanctions of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting these systems of inequality. This what our constitution does. The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, casts, sex or place of birth. Our Constitution also abolished the practice of untouchability. Most modern Constitutions and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, race and religion or gender.

- (a) What does the government do to establish equality? 2
- (b) What is meant by 'Equality before law'? 2
- (c) Which article of Constitution abolishes untouchability? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। चूँकि ऐसी बहुत-सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करें। हमारे संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतान्त्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना 'सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव' के रूप में समाहित किया।

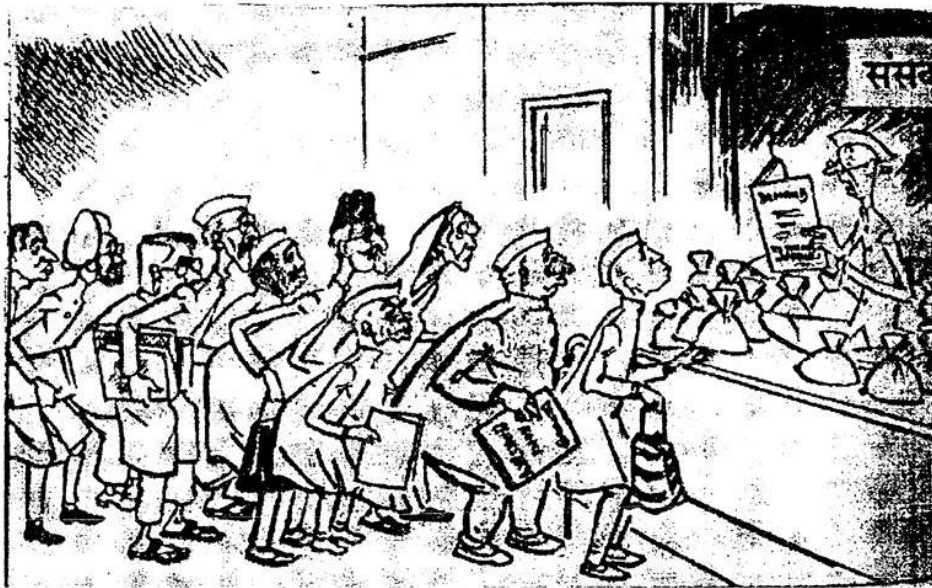
- (a) समानता की स्थापना के लिए सरकारों ने क्या किया है?
- (b) 'कानून के समक्ष समानता' से क्या अभिप्राय है?
- (c) संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है?

20. Study the cartoon given below carefully and answer the following questions :

- (a) Who are the people standing in front of the stage ?
- (b) Why are these people standing here and why are they looking very humble ?
- (c) Which Parliamentary power does this cartoon reflect ?

उपरोक्त दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

- (a) मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति कौन हैं ?
- (b) ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हैं तथा इतने दीन-हीन (विनम्र) क्यों दिख रहे हैं ?
- (c) कार्टून संसद की किस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है ?



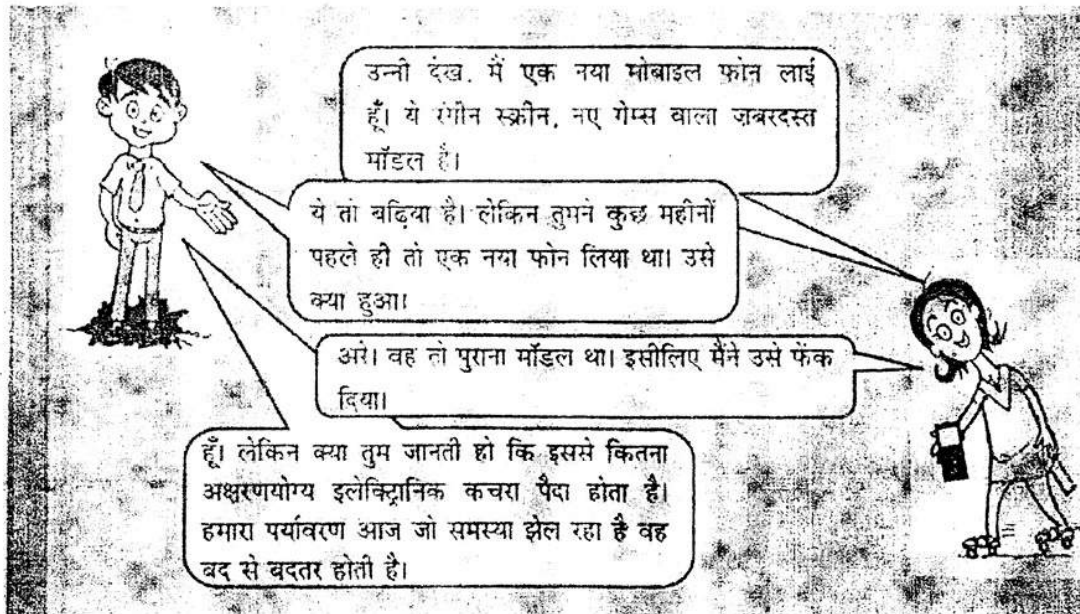
21. Study the picture given below and answer the following questions :

- (a) What is meant by development ? 2
- (b) What are the problems of developing countries ? 1
- (c) Apart from electronic waste, which factors are responsible for damage of environment ? 2

दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

- (a) विकास से आप क्या समझते हैं ?

- (b) विकासशील देशों की समस्याएँ क्या हैं ?
- (c) इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अतिरिक्त किन कारणों से पर्यावरण को हानि होती है ?



22. "India is a sovereign, secular, democratic republic." Explain.

6

“भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य है।” व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

“The Constitution of India is a bag of borrowings.” Discuss.

“भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है।” व्याख्या कीजिए।

23. Distinguish between political executive and permanent executive.

6

राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर लिखिए।

OR / अथवा

Discuss the functions and powers of the Prime Minister.

प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

24. Discuss the amending procedure of Indian Constitution.

6

भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

“Indian Constitution is a blend of rigidity and flexibility.” Explain and discuss.

“भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है।” व्याख्या कीजिए।

Discuss the scope of Political Science.

6

राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

Discuss the importance of political theory.

राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए।

Distinguish between a citizen and an alien.

6

नागरिक और विदेशी में क्या अन्तर है?

OR / अथवा

How can citizenship be lost. Write in detail.

नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है? विस्तारपूर्वक बताइए।

Is India a secular state? Give arguments in support of your answer.

6

क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

OR / अथवा

Discuss the factors that establish the independence of judiciary.

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए।

Marking Scheme

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI

[M. M. : 100]

-
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. हम आदेश देते हैं। | 1 |
| 2. अमरीका के संविधान से। | 1 |
| 3. युद्ध की अनुपस्थिति। | 1 |
| 4. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। | $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ |
| 5. United Nations Development Programme.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। | 1 |
| 6. संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन 'प्रश्नकाल' आता है जिसमें सांसदों द्वारा विभिन्न विषयों या मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों को देने होते हैं। | 2 |
| 7. प्रारंभिक, अपीलीय, सलाहकारी, मौलिक अधिकारों का रक्षक, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण। (किन्हीं दो का विस्तार) | 1 + 1 |
| 8. (i) भारतीय संविधान लिखित व कठोर है।
(ii) केन्द्र व राज्य की शक्तियों का बटवारा संविधान द्वारा किया गया है।
(iii) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। (अथवा अन्य कोई भी विशेषता) | 1 + 1 |
| 9. समय, परिस्थितियों व आवश्यकताओं के साथ परिवर्तनशील है, गतिशील है, या अन्य कोई तर्क। | 2 |
| 10. (i) मौलिक अधिकार देश के संविधान में होते हैं प्राकृतिक अधिकार नहीं।
(ii) मौलिक अधिकार न्याय संगत है जबकि प्राकृतिक अधिकार नहीं।
(iii) प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में संभव हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य में उपलब्ध होते हैं। (कोई दो) | 1 + 1 |
| 11. मतदाता सूचियों को तैयार करना
चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना
चुनाव का निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण
चुनाव करवाना
उप-चुनाव करवाना
चुनाव चिन्ह प्रदान करना | 4 × 1 |
| | (अथवा अन्य कोई 4) |

12. शक्तियों के बँटवारे में अधिक शक्तियाँ दी जाए जैसे पंजाब और तमिलनाडु सरकारों ने अधिक वित्तीय अधिकार। 4 × 1
प्रशासकीय विषयों पर केन्द्र का कम नियंत्रण।
हिन्दी भाषा को गैर हिन्दी भाषीय राज्यों में लागू न किया जाए।
अन्य भाषाओं व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए।
राज्यपालों को राज्यों की सलाह से नियुक्त किया जाए। (कोई चार)
13. स्थानीय स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। 4 × 1
तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था
ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा
पंचायतों की रचना
सदस्यों का चुनाव
पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में
सीटों का आरक्षण (या अन्य कोई चार, संक्षिप्त विवरण)
14. प्लेटो के अनुसार जिसका जिसको प्राप्त है वह देना ही न्याय है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम कल्याण है। और न्याय का अर्थ भी व्यक्ति को प्राप्य है वही देय है। वर्तमान में व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के अवसर प्राप्त हों। सभी के साथ समानता का व्यवहार व अवसरों की समानता हो। (विस्तृत विवरण) 4
15. राज्य के चार अनिवार्य तत्व हैं, राष्ट्र के अनेक तत्व हैं। 4 × 1
राष्ट्र के लिए एकता की भावना अनिवार्य, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए निश्चित भू-भाग आवश्यक, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य, राष्ट्र के लिए नहीं। (या अन्य कोई 4)
16. विश्व शांति व सुरक्षा के लिए। 4 × 1
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए।
युद्धों की भीषणता कम करने के लिए।
विश्व के आर्थिक विकास के लिए।
सैन्यीकरण व युद्धों को रोकने के लिए।
मानवजाति के कल्याण के लिए। (या अन्य कोई 4 संक्षिप्त विवरण सहित)
17. (i) 6 1
(ii) संविधानिक उपचारों का अधिकार। 1
(iii) व्यक्ति, निजी संगठनों तथा सरकार के विभिन्न अंगों से। 3
18. (i) अनैतिक व निरंकुश प्रतिबन्धों सहित स्वतन्त्रता। 2
(ii) सभी प्रतिबन्धों का अभाव ही नकारात्मक स्वतन्त्रता है। 2
(iii) निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतन्त्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। (i, ii - संक्षिप्त विवरण सहित)

19. (i) बिना किसी धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के भेद के भेदभाव का निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता की स्थापना।
- (ii) कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई की कानून से ऊपर या विशेष नहीं है। राज्य भी सभी के लिए एकसा कानून बनाएगा बिना किसी भेदभाव, सभी पर साधारण न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा, व्यक्ति चाहे कोई भी हो।
- (iii) अनुच्छेद 17 (समानता के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत)
20. (i) विभिन्न मन्त्रालयों के मन्त्रिगण। 1
- (ii) मन्त्रालयों के लिए धन आबंटित कराने के लिए, संसद से स्वीकृति के पश्चात ही धन आबंटित हो सकता तथा ये कार्य विनम्रता से ही संभव हैं। 2
- (iii) संसद की कराधान तथा धन के प्रयोग पर नियन्त्रण की शक्ति। 2
21. (i) विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। 2
- (ii) औद्योगिक विकास, गरीबी, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि (या अन्य कोई) 1
- (iii) भूमण्डल का ताप बढ़ना, कृषि योग्य भूमि कम होना, जल प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन। (या अन्य कोई) 2
22. प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक तथा गणराज्य शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या। 6

अथवा

संविधान निर्माताओं ने खुले दिल से दूसरे देशों के संविधान के गुणों को संचित किया इसी कारण आलोचकों द्वारा संविधान के बारे में ऐसा कहा गया है पर वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण पर अनेक तत्वों का योगदान रहा है।

ब्रिटिश संविधान—शक्तिशाली लोकसभा, राष्ट्रपति मुखिया संसदीय शासन प्रणाली, एकीकृत ढांचा।

अमरीकी संविधान—मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण, संघात्मक ढांचा।

आयरलैंड, कनैडियन, जर्मन, आस्ट्रेलिया के संविधानों का प्रभाव बताते हुए छत्र भारतीय संविधान की मूल-भूत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्षतः उसे भारतीय स्थितियों के अनुकूल प्रस्तुत करेंगे।

23. नियुक्ति सम्बन्धी, योग्यता, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, राजनीतिक सम्बंधों, भूमिकाओं तथा परस्पर सम्बन्धों से सम्बन्धित। 6
(संक्षिप्त व्याख्या सहित)

अथवा

मन्त्रिमण्डल के नेता के रूप में—मन्त्रिपरिषद का निर्माण। विभागों का विभाजन मन्त्रिमण्डल का सभापति, मन्त्रियों का हटाना। समन्वयकारी रूप, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण कड़ी, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, संसद का नेता, नियुक्तियाँ, विदेशी नीतियों का निर्माता, संकटकालीन शक्तियाँ। (संक्षिप्त वर्णन सहित)

24. अनुच्छेद 308 में संशोधन की दो विधियों का वर्णन है। परन्तु ये तीन विधियों से होता है। 6
- (i) संसद द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना।
- (ii) संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन है दोनों सदनों में कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संभव।
- (iii) संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधान पालिकाओं के अनुमोदन द्वारा संशोधन—इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, और चुनाव विधि, केन्द्र व राज्यों के वैधानिक सम्बन्ध, संघीय सरकार व राज्य सरकारों की कार्य-पालिका सम्बन्धी शक्तियों की सीमा इत्यादि। (विस्तारपूर्वक वर्णन)

अथवा

इसके कुछ भागों में सरलता, कुछ में कठिन व कुछ भागों में कठिनतम तरीके से ही बदलाव संभव है। इसी लिये ऐसा कहा गया है। छात्र इस में संशोधन विधियों की व्याख्या तथा संशोधन के विषय क्षेत्र सहित विस्तारपूर्वक लिखेंगे।

25. राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, शासन प्रबन्ध का अध्ययन, समुदायों तथा संस्थानों का राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व संगठनों तथा सम्बन्धों, नेतृत्व का, राजनीतिक दलों, सत्ता व शक्ति का अध्ययन।
(संक्षिप्त किन्हीं छः का वर्णन)

अथवा

राजनीतिक वास्तविकता को समझने में सहायक, ज्ञान का सरलीकरण करना, व्यावहारिक दक्षताओं का विकास, समस्याएं सुलझाने में सहायक, शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करना, बुद्धि का विस्तार, राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा, सामाजिक परिवर्तन को समझने व व्याख्या के लिए सहायक।
(किन्हीं छः का संक्षिप्त परिचय) 1 × 6

26. (1) नागरिक राज्य का होता है विदेशी राज्य का सदस्य नहीं 6 × 1
(2) राज्य भक्ति के आधार पर
(3) अधिकारों के आधार पर
(4) सैनिक सेवा के आधार पर
(5) न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर
(6) प्रकारों के आधार पर (संक्षिप्त अर्थ व विस्तार)

अथवा

लम्बे समय तक अनुपस्थिति, विवाह, विदेश में सरकारी नौकरी, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग, पराजय द्वारा, सेना से भाग जाने पर, देशद्रोह, गोद लेना, विदेश सरकार से सम्मान प्राप्त करना, विदेश में संपत्ति खरीदना। (कोई छः अर्थसहित)

27. स्वतन्त्रता के पश्चात भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। इसकी विशेषताएँ प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य की दृष्टि में सब धर्म समान, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार, सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मनाही, छुआछूत की समाप्ति इत्यादि इसे सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है।
(उपरोक्त बिन्दुओं की संक्षिप्त व्याख्या) 6

अथवा

- (1) न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा 6
(2) नौकरी की सुरक्षा
(3) लम्बा कार्यकाल
(4) अच्छा वेतन तथा पेंशन
(5) सेवा की शर्तों में हानिकारक परिवर्तन न होना
(6) न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएँ
(7) रिटायर होने के पश्चात् वकालत की मनाही
(8) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। (कोई छः)

सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, मार्च – 2016
मूल्यांकन योजना-राजनीति विज्ञान
अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिन्दु
59/1/1

प्र0 1. उ0	<p>बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ?</p> <p>a. यह पूँजीपति तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। b. इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात् किया गया। c. लोगों द्वारा इसे 9 नवम्बर, 1989 को तोड़ दिया गया। d. यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था।</p> <p>यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था।</p>	1
प्र0 2. उ0	<p>आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना क्यों की गई ? आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना के कारण :</p> <p>(i) आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने के लिए। (ii) सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। (iii) क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए।</p>	1
प्र0 3. उ0	<p>दोनों में से अधिक अनिवार्य कौन सा है और क्यों – बड़े बाँधों का निर्माण अथवा इसका विरोध करने वाले पर्यावरण संबंधी आंदोलन ?</p> <p>परीक्षार्थी दिए हुए विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में लिख सकता है – परन्तु उसके उत्तर के साथ तर्क होना चाहिए। जैसे –</p> <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बांधों का निर्माण आवश्यक है अथवा बांधों का निर्माण लोगों के विस्थापन और पर्यावरण का निम्नीकरण करता है। अतः इसके विरुद्ध आंदोलन आवश्यक है। 	1
प्र0 4. उ0	<p>गुट-निरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू किन दो लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहते थे ?</p> <p>(i) कठिनाई से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा। (ii) क्षेत्रीय अखण्डता और एकता को बनाए रखना। (iii) तांत्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।</p> <p style="text-align: right;">(कोई दो)</p>	2x½=1
प्र0 5. उ0	<p>चिपको आंदोलन के सर्वाधिक अनूठे पहलू को उजागर कीजिए।</p> <p>महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर</p>	1
प्र0 6. उ0	<p>शीत युद्ध की किन्हीं दो प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।</p> <p>(i) दो महाशक्तियों के नेतृत्व में दो सैन्य गुटों का होना। (ii) महाशक्तियाँ युद्ध लड़ने के खतरों अर्थात् महाविनाश से परिचित थीं। अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर</p>	2x1=2

प्र० 7.	“स्वतंत्र भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे; वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे।” आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ?	
उ०	परीक्षार्थी को उत्तर के पक्ष में तर्क/तथ्य/उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण के लिए : स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने राजनीति को चुना और लोगों की समस्याएं हल करने के लिए सत्ता में आने का प्रयास किया। अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	2
प्र० 8.	निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए : ‘A’ (a) राजनीति से प्रेरित विवादास्पद नियुक्ति (b) 1947 में रेलवे की हड़ताल का नेतृत्व किया (c) नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होना से इंकार (d) पुलिस हिरासत में मौत ‘B’ (i) चारु मजूमदार (ii) जय प्रकाश नारायण (iii) जार्ज फर्नांडिस (iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे.	
उ०	(a) (iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे. (b) (iii) जार्ज फर्नांडिस (c) (ii) जय प्रकाश नारायण (d) (i) चारु मजूमदार	4x½=2
प्र० 9.	हालांकि 1950 के दशक में, देश के शेष हिस्सों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी ?	
उ०	‘पंजाबी सूबा’ आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था और इस आंदोलन को गैर सिक्खों और सिक्खों में भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलनों जैसा मजबूत नहीं था।	2
प्र० 10.	पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे और कब तक पूरा किया गया ? उत्तर-पूर्व राज्यों का पुनर्गठन लगभग 1972 में पूरा हो गया था, जैसे 1972 में आसाम में से एक क्षेत्र ले कर मेघालय बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा भी इसी वर्ष अलग राज्य के रूप में उभरे। परन्तु अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना जबकि नागालैण्ड 1963 में ही बन गया था।	
उ०		2
प्र० 11.	चीन की नई आर्थिक नीति ने किन चार तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया ?	
उ०	(i) जड़ता को समाप्त करके (ii) कृषि के निजीकरण से (iii) व्यापार के नए नियम और नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण द्वारा (iv) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ने की तीव्र वृद्धि दर से	4x1=4

प्र0 12.	<p>एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ? इसके मुख्य कार्य लिखिए।</p>	
उ0	<ul style="list-style-type: none"> • एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है। • कार्य : <ul style="list-style-type: none"> (i) यह मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। (ii) यह सरकारी अधिकारियों के दुर्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करता है। (iii) यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। (iv) अन्य कोई प्रासंगिक बिन्दु। 	1+3=4
प्र0 13.	<p>वैश्विक संपदा से क्या अभिप्राय है ? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं है ?</p>	
उ0	<ul style="list-style-type: none"> • विश्व की सांझी सम्पदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। • ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि : <ul style="list-style-type: none"> (i) एक सर्व-सम्मत प्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। (ii) बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबन्धन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। (iii) बाहरी अंतरिक्ष में हो रहे दोहन कार्यों का लाभ न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। <p style="text-align: right;">(कोई दो कारण)</p>	2+2=4
प्र0 14.	<p>भारत की कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एकदलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न है ? स्पष्ट कीजिए।</p>	
उ0	<p>यह निम्नलिखित कारणों से भिन्न है :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम नहीं हुआ है। (ii) भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थी जबकि चीन और रूस जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व एकल पार्टी व्यवस्था के कारण था। (iii) भारत में म्यांमार और बेलारूस की तरह एक पार्टी का प्रभुत्व सैन्य दखलान्दजी के कारण नहीं था। (iv) भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व उसकी अपनी लोकप्रियता के कारण था। 	4
प्र0 15.	<p>भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।</p>	
उ0	<p>भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणाम :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) कृषि, व्यापार और उद्योगों का अधिकांश भाग निजी हाथों में छोड़ दिया गया। (ii) राज्य द्वारा नियंत्रित मुख्य भारी उद्योगों ने औद्योगिक ढांचे, नियमित व्यापार और कृषि में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। 	

	इससे निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई और इसने भावी विकास को आधार किया।	4
प्र० 16.	1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया ? व्याख्या कीजिए।	
उ०	<p>जनता पार्टी ने 1977 के चुनावों को निम्नलिखित ढंग से जनमत संग्रह में बदला :</p> <p>(i) सभी विरोधी दलों ने कांग्रेस के विरुद्ध आपस में हाथ मिलाकर जनता के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखा।</p> <p>(ii) जनता पार्टी ने लोकतंत्र की वकालत की तथा आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया।</p> <p>(iii) जयप्रकाश नारायण विपक्ष का चेहरा बन गया और जे. पी. एंव इन्दिरा के बीच एक को चुनने का विकल्प बन गया।</p> <p>(iv) जनता पार्टी ने लोगों को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच किसी एक को चुनने का आह्वान किया।</p>	4
प्र० 17.	<p>दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-</p> <p>हर देश को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि इस दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। 'शॉक थेरेपी' की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिलिकियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढाँचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। 'सामूहिक फार्म' को 'निजी फार्म' में बदला गया और पूँजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या 'तीसरे रूख' को मंजूर नहीं किया गया।</p> <p>i. ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जिन्हें अपनी व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन लाना था।</p> <p>ii. सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में क्यों बदला जाना था ?</p> <p>iii. क्योंकि किसी तीसरे रास्ते की कोई सम्भावना नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पहले दो रास्ते कौन से थे ?</p>	
उ०	<p>(i) आर्मीनिया, जार्जिया, उज़्बेकिस्तान अथवा सोवियत संघ के विघटन के बाद बना कोई अन्य देश। (कोई दो देश)</p> <p>(ii) राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की समाप्ति एवं निजीकरण और उदारीकरण के लागू होने के कारण।</p> <p>(iii) a) राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था (समाजवाद) b) पूँजीवाद</p>	1+2+2=5
प्र० 18.	<p>दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:</p> <p>सबसे सीधा-सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछेक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक-कल्याणकारी</p>	

उ०	<p>कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक-कल्याण होता था। लोक-कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाज़ार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 'राज्य की क्षमता में कमी आना' एक उदाहरण द्वारा इन शब्दों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। 'कल्याणकारी राज्य' की धारणा का स्थान 'न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य' क्यों ले रहा है ? बाज़ार किस प्रकार सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है ? <p>(i) वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानि सरकारों को जो काम करना है, उसे करने की ताकत में कमी आती है। आजकल विभिन्न देशों की सरकारों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है।</p> <p>(ii) निजीकरण के कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में आ गई हैं। राज्यों की भूमिका आर्थिक विकास में सहायता करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है।</p> <p>(iii) बहुराष्ट्रीय कंपनियां आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में आ गई हैं। उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजारों की तलाश है। अतः अब बाजार सामाजिक प्राथमिकताओं के निर्धारक बन गए हैं।</p>	2+2+1=5
उ०	<p>प्र० 19. दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:</p> <p>भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब-इज़रायल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई।</p> <ol style="list-style-type: none"> भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया और क्यों ? भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, उस काल को भारत की घरेलू राजनीति का, सबसे कठिन काल क्यों समझा जाता है ? 1970 के दशक के प्रारंभ में घटित किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के कारण भारत में मँहगाई बहुत बढ़ गयी थी ? <p>(i) मई 1974 में – आणविक ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, प्रयोग करने के लिए।</p> <p>(ii) अरब – इज़रायल युद्ध के कारण कीमतें बढ़ रही थीं। अतः भारत आर्थिक मोर्चे पर संकटों का मुकाबला कर रहा था।</p> <p>(iii) 1973 का अरब – इज़रायल युद्ध।</p>	2+2+1=5
प्र० 20.	नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।	

उ०	<p>i. दिए गए कार्डून से किन्हीं चार राष्ट्रीय नेताओं की पहचान कीजिए तथा प्रत्येक की क्रम संख्या भी लिखिए।</p> <p>ii. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेता न. 2 के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या था ?</p> <p>iii. 1989 के लोकसभा निर्वाचन में, क्रम संख्या एक के नेतृत्व वाले दल की स्थिति क्या थी ?</p> <p>i. 1 राजीव गांधी 2 वी. पी. सिंह 3 लाल कृष्ण आडवानी 4 देवी लाल 5 ज्योति बसु 6 चन्द्र शेखर 7 एन. टी. रामा राव 8 पी. के. मोहन्तो 9 के. करुणानिधि (कोई चार)</p> <p>ii. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना।</p> <p>iii. 1989 में पार्टी बुरी तरह प्रभावित हुई तथा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। (415, सांसदों से घट कर 189 पर पहुँच गई थी)</p>							
उ०	<p>नोट:- निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 20 के स्थान पर हैं।</p> <p>20.1 1984 के लोकसभा निर्वाचन में किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीतीं और किसके नेतृत्व में ?</p> <p>20.2 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने कौन सा सर्वाधिक विवादास्पद निर्णय लिया ?</p> <p>20.3 किस प्रधानमंत्री ने नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की तथा इसका क्या परिणाम निकला ?</p> <p>20.1 (i) कांग्रेस पार्टी (ii) राजीव गांधी के नेतृत्व में</p> <p>20.2 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना।</p> <p>20.3 नए आर्थिक सुधार राजीव गांधी द्वारा लागू किए गए। इसने आर्थिक नीति की दिशा को यकायक बदल दिया।</p>	<p>2+1+2=5</p> <p>2+1+2=5</p>						
प्र० 21.	<p>दिए गए दक्षिण एशिया के रेखा-मानचित्र में, पाँच देशों को A, B, C, D तथा E द्वारा चिह्नित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और उत्तरपुस्तिका में उनके सही क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर, नीचे दी गई तालिका के रूप में लिखिए।</p> <table border="1" data-bbox="284 1478 1252 1608"> <tr> <th>प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या</th><th>संबंधित अक्षर</th><th>देश का नाम</th></tr> <tr> <td>(i) से (v) तक</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>i. एक महत्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण एशिया का भाग नहीं समझा जाता।</p> <p>ii. इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही है।</p>	प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम	(i) से (v) तक			
प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम						
(i) से (v) तक								

- iii. इस देश में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के शासक रहे हैं।
iv. वह देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है।
v. एक द्वीपीय राष्ट्र जो 1968 तक एक सल्तनत था।

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम
(i)	B	चीन
(ii)	D	श्रीलंका
(iii)	E	बांग्लादेश
(iv)	A	नेपाल
(v)	C	मालदीव

5x1=5

नोट:- निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 21 के स्थान पर है।

- 21.1 दक्षिण एशिया में प्रायः कौन-कौन से देश शामिल किए जाते हैं ?
21.2 दक्षिण एशिया के कौन से दो देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है।
21.3 दक्षेस (SAARC) तथा साफ्टा (SAFTA) के विस्तृत रूप लिखिए।

- 21.1 बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान
नोट: यदि परीक्षार्थी अफगानिस्तान नहीं लिखता है तब भी उसे अंक दिए जाएं।
21.2 श्रीलंका और भारत
21.3 दक्षेस (SAARC) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकारी संगठन
साफ्टा (SAFTA) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार-क्षेत्र समझौता

2+1+2=5

प्र0 22.

सोवियत संघ व्यवस्था की किन्हीं तीन सकारात्मक तथा तीन नकारात्मक विशेषताओं को उजागर कीजिए।

उ0

सकारात्मक विशेषताएं :

- (i) सोवियत व्यवस्था अमेरीका को छोड़कर शेष पूरे विश्व से कहीं अधिक विकसित थी।
(ii) सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था।
(iii) सरकार द्वारा बुनियादी जरूरत की चीजों जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाना।
(iv) बेरोजगारी का न होना।

अन्य कोई सकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं)

नकारात्मक विशेषताएं :

- (i) व्यवस्था सत्तावादी थी और नौकरशाही का कड़ा शिकंजा था।
(ii) लोकतंत्र की कमी और अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता का न होना।
(iii) केवल एक दलीय व्यवस्था का होना।
(iv) पार्टी द्वारा लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अवहेलना।

अन्य कोई नकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं)

3+3=6

<p>उ0</p>	<p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>यह कहना कहाँ तक उचित है कि शीत युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों की लाभ हानि के गणित से होता था ? व्याख्या कीजिए।</p> <p>यह कथन महाशक्तियों तथा उनके गठबंधन के बारे में बिल्कुल ठीक है।</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) महाशक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके देशों को अपने पक्ष में किया : (ii) सोवियत संघ ने अपने गुट (गठबंधन) के देशों की बड़ी सेनाओं के बल पर पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का प्रयोग किया। (iii) दूसरी ओर अमरीका ने सीटो और सेन्टो जैसे गठबंधन बनाए तथा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ सोवियत संघ और चीन ने अपने संबंध मजबूत किए। (iv) महत्वपूर्ण संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए गठबंधन बनाए गए। (v) महाशक्तियों को अपने हथियारों के संचालन के लिए भू-क्षेत्रों की आवश्यकता थी। (vi) आर्थिक मदद एक अन्य मुद्दा था। <p>उत्तर के पक्ष में अन्य कोई बिन्दु</p>	<p>6x1=6</p>
<p>प्र0 23.</p> <p>उ0</p> <p>उ0</p>	<p>संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के सम्बन्ध किस प्रकार के होने चाहिए। इसके बारे में, भारत के अंदर तीन विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण कीजिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) भारत को अमरीका से अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और उसे अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। (ii) भारत को अमरीकी वर्चस्व और आपसी समझ का यथा संभव अपने हित में लाभ उठाना चाहिए। अमरीका का विरोध करना व्यर्थ होगा और अंततः भारत को क्षति पहुंचेगी। (iii) भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बनाने में नेतृत्व देना चाहिए। <p>अन्य कोई दृष्टिकोण</p> <p style="text-align: right;">(कोई तीन व्याख्या सहित)</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ऐसे किन्हीं तीन प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल कर, एक राजनैतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक कदम बढ़ाना था। (ii) 1957 में यूरोपीय इकनॉमिक कम्युनिटी के गठन से राजनीतिक चर्चा शुरू हुई जिससे यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ। (iii) सोवियत संगठन के विघटन ने यूरोप में इस प्रक्रिया को तेजी प्रदान की और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ के रूप में हुई। (iv) इसने अपना झंडा, स्थापना दिवस, गान और अलग मुद्रा को अपनाया। (v) विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका अपना राजनीतिक प्रभाव भी है। <p style="text-align: right;">(कोई तीन व्याख्या सहित)</p>	<p>3x2=6</p> <p>3x2=6</p>
<p>प्र0 24.</p>	<p>ऐसे किन्हीं तीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर कार्य करें।</p>	

उ०	<p>अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मुद्दे :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) आतंकवाद (ii) ग्लोबल वार्मिंग / पर्यावरणीय निम्नीकरण (iii) पीने के पानी की कमी (iv) वैश्विक गरीबी (v) संक्रामक रोग <p>अन्य कोई सही मुद्दा</p> <p style="text-align: right;">(कोई तीन का वर्णन)</p>	3x2=6
उ०	<p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है ? इस प्रकार की सुरक्षा के किन्हीं दो तत्त्वों का वर्णन कीजिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> • बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा : किसी देश को सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा माना जाता है। • बाह्य सुरक्षा के तत्व : <ul style="list-style-type: none"> (i) बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करना अथवा उसे रोकना। (ii) युद्ध को टालना। (iii) शक्ति संतुलन / गठबंधन बनाना <p style="text-align: right;">(कोई दो व्याख्या सहित)</p>	2+4=6
प्र० 25.	<p>"क्षेत्रीय माँगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना, एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया।" इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कोई तीन उपयुक्त तर्क दीजिए।</p>	
उ०	<p><u>कथन के समर्थन में तर्क :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 60 वर्षों में भाषायी आधार पर बनने वाले राज्यों ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को सकारात्मक और रचनात्मक बना दिया है। (ii) भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण से राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने में भाषा सभी के लिए एक समान आधार बन गई है। (iii) इससे देश का विघटन के बजाय एकीकरण हुआ है। (iv) लोगों की क्षेत्रीय अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, लोगों को ताकत मिली है और लोकतंत्र सफल हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अनेक क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्थान दिया जा रहा है। <p style="text-align: right;">(कोई तीन व्याख्या सहित)</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति तथा असहमति के विभिन्न क्षेत्रों का परिक्षण कीजिए।</p>	3x2=6
उ०	<p><u>सहमति के क्षेत्र :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए। 	

	<p>(ii) विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता अपितु सरकार को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।</p> <p>(iii) गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के काम को सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी माना गया।</p> <p>असहमति के क्षेत्र :</p> <p>(i) सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति।</p> <p>(ii) यदि आर्थिक वृद्धि से भिन्नता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्त्व पर असहमति।</p> <p>(iii) उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दे पर असहमति।</p>	3+3=6
प्र० 26.	लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात्, इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली किन्हीं चार उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।	
उ०	<p>• इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियाँ :</p> <p>(i) इंदिरा गांधी लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं।</p> <p>(ii) वह 1958 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई थी।</p> <p>(iii) वह 1964-66 में शास्त्री जी के मंत्रीमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थीं।</p> <p>(कोई दो बिंदु)</p> <p>• इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली उपलब्धियाँ :</p> <p>(i) उसने 'गरीबी हटाओ' का लोकप्रिय नारा दिया था।</p> <p>(ii) उसने सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि पर ध्यान दिया।</p> <p>(iii) उसने ग्रामीण भूमि की तथा शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी की जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके।</p> <p>(iv) उसने रज़वाड़ों को दी जाने वाली सुविधाएं कम कीं।</p> <p>(v) 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक जीत।</p> <p>(vi) 1974 में पहला आणविक विस्फोट।</p> <p>(कोई चार बिंदु)</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>25 जून, 1975 को भारत में आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए।</p>	2+4=6
उ०	<p>आपातकाल लागू करने की परिस्थितियाँ :</p> <p>(i) न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संघर्ष।</p> <p>(ii) वृद्धि दर में कमी और कीमतों का बढ़ना।</p> <p>(iii) बिहार और गुजरात में मंहगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र आंदोलन।</p> <p>(iv) जॉर्ज फर्नांडीज़ के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल।</p> <p>(v) रामलीला मैदान की विशाल रैली जहां जयप्रकाश नारायण ने कर्मचारियों से सरकार के अवैध आदेश न मानने का आग्रह किया।</p> <p>(vi) इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने का निर्णय।</p>	6

प्र० 27.	भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जाने वाले किसान आंदोलन को, सर्वाधिक सफल जन आंदोलन बनाने वाले किन्हीं छः कारकों का वर्णन कीजिए।	
उ०	<p>i. भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चला यह आंदोलन बहुत ही अनुशासित था।</p> <p>ii. भारतीय किसान यूनियन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए 'जाति पंचायत' की परम्परागत संस्था का उपयोग किया।</p> <p>iii. धनराशि एवं संसाधन जुटाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने इसी जातिगत-वंशगत सम्पर्क जाल का प्रयोग किया।</p> <p>iv. भारतीय किसान यूनियन की मांगे किसानों की चिर प्रतीक्षित मांगे थीं और उनके हित में थीं। इसलिए किसानों द्वारा तुरन्त स्वीकार कर ली गई।</p> <p>v. भारतीय किसान यूनियन ने स्वयं को अराजनीतिक रखा और एक दबाव समूह के रूप में काम किया।</p> <p>vi. भारतीय किसान यूनियन ने दबाव की नीति प्रयोग की और किसानों की शक्ति का प्रदर्शन किया।</p> <p>अन्य कोई उपयुक्त बिंदु</p> <p>अथवा</p> <p>क्षेत्रीय आकांक्षाएँ तथा उनकी पूर्ति लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। इस विचार से मिलने वाली किन्हीं तीन शिक्षाओं का वर्णन कीजिए।</p>	6x1=6
उ०	<p>i. क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करना सामान्य है।</p> <p>ii. क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं और संवाद सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं।</p> <p>iii. क्षेत्रीय मुद्दों को सत्ता की साझेदारी के माध्यम से संवैधानिक ढांचे में ही हल किया जा सकता है।</p> <p>iv. क्षेत्रीय संतुलन और आर्थिक विकास से भेदभाव की भावना में कमी आती है। अतः क्षेत्रों के पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के प्रयास होने चाहिए।</p> <p>v. संवैधानिक प्रावधानों में ही क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के प्रावधान पहले से ही निहित हैं। संविधान की छठी अनुसूची विभिन्न कबीलों (जन जातियों) को अपनी प्रथाओं और पारम्परिक कानूनों को संरक्षित रखने की अनुमति देती है।</p> <p>vi. संघवाद का सही अर्थों में सम्मान होना चाहिए।</p> <p>अन्य कोई उपयुक्त शिक्षा</p> <p>(कोई तीन बिंदु)</p>	3x2=6

पाठ-1

राष्ट्रवाद

परिचय

राष्ट्र निर्माण का मूल आधार राष्ट्रवाद है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो लोगों में एकता की भावना स्थापित करती है। जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा एशिया और अफ्रीका के लोगों का उपनिवेशवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रहा है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का एक अन्य पक्ष यह दर्शाता है कि एकता के साथ-साथ यह इतिहास में विघटन का कारण भी रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में एकता का भाव उनकी कौन सी पहचान के कारण पैदा हुआ है। धर्म आधारित राष्ट्रीयता के विचार का आधार बना कर मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के विभाजन की पेशकश की। जबकि 1971 में मुस्लिम बहुल पाकिस्तान का विभाजन भाषायी व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण हुआ। और पूर्वी पाकिस्तान एक नए राष्ट्र 'बांग्लादेश' के रूप में स्थापित हुआ। अतः राष्ट्रवाद को परिभाषित करना सरल नहीं है। यह एक ऐसी मनः स्थिति

जिसमें लोग अपनेपन और जुड़ाव को महसूस करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इसके कारक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

अधिगम परिणाम

- (1) राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति एवं विकास को समझ सकेंगे।
- (2) राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझ सकेंगे।
- (3) राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रीयवाद तथा साम्राज्यवाद के सम्बन्ध को समझना।
- (4) राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं की स्वीकार करना।
- (5) लोकतन्त्र एवं राष्ट्रवाद के बीच सम्बन्ध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ होना।
- (6) अधिकार के भाव को समझना।
- (8) राष्ट्रवाद और बहुलवाद में सम्बन्ध स्थापित करना।

राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद—राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की कोई मानक परिभाषा प्रस्तुत करना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। या तो इन शब्दों का प्रयोग पर्याय रूप में या फिर विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न रूपों में किया जाता है।

राष्ट्र जनता का कोई आकास्मिक समूह नहीं है। लेकिन यह समाज में पाये जाने वाले अन्य समूहों या समुदायों से अलग है। यह प्रत्यक्ष सम्बन्धों पर आधारित परिवार से जनजातीय, जातीय और अन्य सगोत्रीय समूहों में भी अलग है क्योंकि इस समूहों के सदस्य आपस में एक-दूसरे को जानते हैं किन्तु राष्ट्रवाद के सदस्य एक-दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से न जानते हुए भी अपनेपन के भाव से जुड़े होते हैं राष्ट्रवाद को मातृभूमि से प्रेम अथवा देशभक्ति का पर्याय माना जाता है। एकता के कठिन बन्धन से बन्धे लोगों का यह समूह हो सकता है जो प्रभुता-सम्पन्न के साथ-साथ विदेशी जुए से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा हो।

इस प्रकार राष्ट्रवाद का निहितार्थ सामान्य राजनैतिक संवेग से है जो प्रभुतासम्पन्न राजनैतिक राज्य का समरूपी माना जाता है।

सामान्यतः माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल, नस्ल, भाषा, धर्म, या जातीयता जैसी कुछ निश्चित पहचान में सहभागी होते हैं किन्तु उपर्युक्त तत्व वर्तमान राजनीति-विज्ञान में राष्ट्रवाद के गठन के लिए इतना महत्त्व नहीं रखते। कोई ऐसा विशिष्ट गुण नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो कई राष्ट्रों में एक सामान्य भाषा नहीं है जैसे कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा-भाषी लोग रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएँ बोलने वाले लोग साथ-साथ रहते हैं।

इस प्रकार से राष्ट्रवाद राष्ट्र का ही वैचारिक प्रति रूप है राष्ट्र को बार्कर के मत में इस प्रकार समझा जा सकता है कि “राष्ट्र किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों का निकाय है जो सामान्य रूप से विभिन्न नस्लों से सम्बन्धित होने पर भी अपने साझे इतिहास की धारा से अर्जित विचारों व भावनाओं में समान भागीदारी रखते हैं। यद्यपि? वह वर्तमान की अपेक्षा अतीत में अधिक, समान धार्मिक विश्वास की साझी विरासत सम्मिलित करते हैं तथा साझे विचारों व भावनाओं के अतिरिक्त सामान्य इच्छा भी रखते हैं और उसके अनुरूप उस इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए अपने पृथक राज्य का निर्माण करते हैं। या उसका प्रयास करते हैं।”

निष्कर्षतः राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है।

राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व—

राष्ट्र के तत्व

- अनिवार्य तत्व
 - साझे विश्वास तथा भावनाएं
 - साझी विरासत तथा संस्कृति
 - साझी राजनैतिक आकांक्षाएँ
 - साझा भू-क्षेत्र
- कुछ गौण तत्व
 - सामान्य जातीय और रक्त सम्बन्ध
 - समान धर्म
 - समान भाषा
 - साझा इतिहास

राष्ट्रवाद के या राष्ट्र की स्थापना के उपर्युक्त तत्वों को विस्तार पूर्वक इस प्रकार समझा जा सकता है।

(1) सांझे विश्वास तथा भावनाएँ—राष्ट्र पर्वतों या भवनों की तरह स्थूल नहीं होते बल्कि यह सांझे विश्वासों और भावनाओं जैसे सूक्ष्म तत्वों पर आधारित होते हैं। जिन्हें देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। किसी राष्ट्र का नागरिक कहीं भी निवास करे किन्तु भावनाओं के माध्यम से अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान होने के लिए तैयार रहता है।

राष्ट्र की तुलना एक टीम से भी की जा सकती है, जो एक साथ काम करते हों या खेलते हों और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हों। अगर वे अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते तो एक टीम की उनकी भावना और हैसियत जाती रहेगी और वे खेल खेलने या काम करने वाले महान् पृथक-पृथक व्यक्ति रह जाएंगे।

एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक कायम रहेगा जब तक उसके सदस्यों के विश्वास और भावनाएँ एक-दूसरे के साथ हों।

(2) समान विरासत और संस्कृति—अपने को एक राष्ट्र मानने वाले लोग अपनी सांझी स्मृतियों, विवदतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। ये लोग अपने महान् नायकों और नायिकाओं के कार्यों की स्मृति में स्मारक बनाने में गर्व महसूस करते हैं अपने सांझे सांस्कृतिक उत्सवों और त्योहारों का आयोजन करते हैं।

जैसे भारत के लोग महात्मा गाँधी, अशफाकउल्ला खाँ, भगत सिंह आदि को स्मरण करते हैं [वैसे ही स्काउटलैण्ड के लोग बैनकर्वन को, स्विटजरलैण्ड के निवासी विलियम टेल को, फ्रांस के लोगों नेपोलियन को, यूहूदी ज्यावाद (ZIONISM) को स्मरण करके राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में अन्य तत्वों की अपेक्षा यह तत्व अधिक प्रभावी रहा है।

(3) सांझें राजनीतिक आदर्श और आकांक्षाएँ—राष्ट्र के सदस्यों की एक संयुक्त दृष्टि होती है कि वे कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। और अन्य तत्वों के अलावा वे लोकतन्त्र, पंथनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के लोग अपने लिए स्वशासन चाहते हैं भारत में स्वामी दयानन्द द्वारा सुराज से अच्छा स्वराज्य को बताया गया था। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की विस्तारवादी नीतियों के तीव्र विरोध में राष्ट्रीयों को सशक्त किया जिससे जर्मनी इटली, रूस तथा स्पेन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, प्रजातान्त्रिक विचारों के विकास ने राजा से हटकर राष्ट्र के प्रति लोगों को निष्ठावान करके राष्ट्रीयता के आदर्श को उच्च शिखर पर पहुँचाया।

(4) सांझा भू-क्षेत्र—किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में लम्बे समय तक साथ रहने से उसमें एक विशेष प्रेम विकसित होता है जो अपनेपन की भावना को पुष्ट करता है। ये लोग इसके पश्चात् कहीं भी रहें अपनी गृहभूमि को ही स्वर्ग समान मानते रहते हैं जैसे इजराइल के यहूदी लोग। भारत के अप्रवासी लोग भी विदेशों में रहने के पश्चात् भी भारत भूमि से ही प्यार करते हैं।

(5) नस्ल की एकता एवं रक्त सम्बन्ध—नस्ल सम्बन्धी एकता राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। प्रायः एक नस्ल के लोगों में एक राष्ट्र के प्रति लगाव रहता है जिसे वे अपना समझते हैं। उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। सामाजिक विकास की आरम्भिक दशा में राष्ट्र निर्माण में इसका अत्यधिक महत्त्व रहा नस्लीय एकता के कुछ उदाहरण हैं जैसे 1930 के दशक में हिटलर द्वारा यहूदियों पर अत्याचार और नार्डिकों को आर्य बताकर नस्लीय एकता से राष्ट्र को पोषित किया किन्तु वर्तमान में यह तत्व इतना महत्त्व नहीं रखता अमेरिका जैसे देश में आज अनेक नस्लों के लोग सुगठित राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं।

(6) समान धर्म—धर्म भी राष्ट्र निर्माण की एक प्रबल शक्ति रहा है भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान का निर्माण धर्म पर आधारित है। मुस्लिम देशों में धर्म को राष्ट्र के लिए मुख्य तत्व माना जाता है इजरायल राष्ट्र के निर्माण में यहूदी धर्म ही प्रबल तत्व रहा है किन्तु आज यह तत्व भी राष्ट्र निर्माण में गौण हो चला है और भारत जैसे विविध धर्मों वाले देश आज पंथनिरपेक्षता को महत्त्व प्रदान कर रहे हैं।

(7) समान भाषा—भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग परस्पर सम्पर्क स्थापित करते हैं। भाषा भी राष्ट्रों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बांग्लादेश के निर्माण में उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा का विवाद ही था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्लाभाषा अपनाना चाहते थे जबकि पश्चिमी पाकिस्तान उन पर उर्दू भाषा थोपना चाहता था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस कारण राष्ट्र नहीं हैं कि वे राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र तथा सामाजिक रूप से एकता बद्ध हैं, बल्कि इस कारण है कि उनके लोग समान भाषा का प्रयोग करते हैं जो अन्य लोगों की भाषा से भिन्न है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी भाषा पर गर्व करता है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजी तथा फ्रांस फ्रेंच पर। कुछ राष्ट्रों की दो राजभाषाएँ हैं ताकि भाषा सम्बन्धी कोई प्रश्न विवादित न हो जैसे कनाडा में दो राष्ट्रीय भाषाएँ हैं अंग्रेजी और फ्रेंच स्विटजरलैण्ड में चार (स्विस, इटालियन, जर्मन और फ्रेंच) राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। कुछ राष्ट्रों ने अपनी विशेष भाषा विकसित कर ली है और सभी नागरिकों पर थोप दिया है जैसे सोवियत संघ ने रूसी भाषा और इण्डोनेशिया भाषा इस प्रकार राष्ट्रीयता के योगदान में भाषा की समानता वह तत्व है जिसके प्रति लोग अधिक जागरूक होते हैं और दमन के प्रति कट्टरता पूर्व संघर्ष करना चाहते हैं जैसा बांग्लादेश के निर्माण में हुआ।

ऊपर वर्णित एक नहीं अपितु अनेक स्थितियाँ राष्ट्रीयता के निर्माण में अहम् भूमिका निभाते हैं जिसके जरिये राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। और यह सत्य है कि जिसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं उसका सार मुख्यतः भावना का विषय है। इस सबके पश्चात् भी एक प्रश्न अनुत्तरित है

कि आखिर लोग राष्ट्र के रूप में खुद को क्यों निरूपित करते हैं इसका उत्तर हम निम्नलिखित सिद्धान्तों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार बाकी सामाजिक समूहों से अलग प्रत्येक राज्य का एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में गठन होना चाहिए। इस प्रकार वे आत्मनिर्णय का अधिकार माँगते हैं। इस आत्मनिर्णय के दावे में राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह माँग रखता है कि उसका पृथक राजनैतिक इकाई या राष्ट्र के दर्जे के रूप में मान्यता प्रदान की जाए।

नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्यवादी अभियानों ने यूरोप के देशों में राष्ट्रवादी भावना की तीव्र किया अतः वाटरलू की लड़ाई के बाद वियना की कांग्रेस ने 1815 में इस सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की तभी 'एक राष्ट्र एक राज्य के आत्मनिर्णय का सिद्धान्त' सर्वत्र छा गया। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सूत्रों में इसी तत्व पर बल दिया। यूरोप में 'एक संस्कृति एक राज्य' की मान्यता ने भी जोर पकड़ा वसाय की सन्धि से बहुत से छोटे और नव स्वतन्त्र राज्यों का गठन हुआ लेकिन उस समय उठायी जा रही एक संस्कृति एक-राज्य की माँगों को सन्तुष्ट नहीं किया जा सका।

जब एशिया और अफ्रीका के राज्य औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को भी घोषणा की थी।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के दावे कुछ मायनों में तो सही ठहराए जा सकते हैं और कुछ अर्थों में यह अराजकता को जन्म देने वाले होंगे। जिनका समाधान केवल नए राज्यों के गठन में नहीं करना वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतान्त्रिक और समतामूलक बनाने में है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा अलग-अलग संस्कृति और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह-अस्तित्व पूर्वक रह सकें।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में इस बात पर बल दिया कि आत्मनिर्णय का अधिकार एक वाक्यमात्र नहीं है बल्कि यह कार्यवाही का एक आवश्यक सिद्धान्त है जिसकी उपेक्षा भविष्य में राजनेता अपने विनाश के मूल्य पर ही पर ही कर सकेंगे। मार्क्सवादियों ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया।

किन्तु इस सिद्धान्त के गम्भीर दोषों का भी उल्लेख किया जा सकता है। यदि किसी विशेष राष्ट्रीयता के लोगों को स्वनिर्णय के आग्रह का अधिकार दिया गया तो बहुत राज्यों में अराजकता फैल जाएगी। इस प्रकार सिद्धान्त को मानना और न मानना दोनों चुनौतीपूर्ण कार्य ही कहे जाएंगे।

आत्म निर्णय की माँग करने वाले विश्व के कुछ समुदाय

समुदाय का नाम	देश का नाम
(1) बास्क	स्पेन
(2) क्यूबेक प्रान्त में फ्रांसीसी	कनाडा
(3) कुर्द	इराक
(4) क्रैन्ज	म्यांमार(बर्मा)
(5) स्काट्स	ब्रिटेन (जनमत संग्रह में विफल)
(6) तमिल	श्री लंका
(7) पश्तू	पाकिस्तान

कुछ समुदाय जिनकी आत्म निर्णय की माँग को मान लिया गया

समुदाय का नाम	देश का नाम
(1) कटंगा	कांगो राज्य का विघटन
(2) बांग्लादेश	पाकिस्तान का विघटन
(3) पूर्वी तिमोर	इण्डोनेशिया का विघटन
(4) दक्षिण सूडान	सूडान का विघटन

बास्क समुदाय की आत्मनिर्णय की माँग

उपर्युक्त तालिका में बास्क के आत्मनिर्णय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है जिसके अनुसार बास्क, स्पेन का पहाड़ी और समूह क्षेत्र है। तथा इसे स्वायत्ता भी प्राप्त है किन्तु यह समुदाय इससे सन्तुष्ट न होकर अपनी संस्कृति,भाषा और भू-संरचना के आधार पर अलग देश की माँग कर रहे हैं।

स्पेनी तानाशह फ्रैंको ने इस स्वायत्ता में कटौती कर दी। क्या वास्क समुदाय के लोगों की स्वायत्ता की माँग जायज है? या फ्रैंको द्वारा स्वायत्ता में कटौती यह एक चुनौती भरा प्रश्न है।

राष्ट्रवाद और बहुलवाद—‘एक संस्कृति एक राज्य’ के विचार को त्यागते ही यह अनिवार्य हो जाता है कि ऐसे उपाय किये जाए जिससे विभिन्न संस्कृतियाँ और समुदाय एक देश में फल-फूल सकें। आज वैश्वीकरण के युग में अनेक क्षेत्रों और समुदायों में राष्ट्रीय आकाक्षाएं उभर रही हैं। ऐसी मांगों को उदारता और लोकतान्त्रिक ढंग से हल किया जाए अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधानों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए भारत के संविधान में धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं।

राष्ट्रवाद के विविध स्वरूप और उनकी संक्षिप्त व्याख्या

- (1) रूढ़िवादी राष्ट्रवाद जो कुछ परम्परागत है उसके प्रति निष्ठा व भक्ति
- (2) उदारवादी राष्ट्रवाद वैयक्तिक स्वतन्त्रता के नाम पर राष्ट्रवाद का गठन
- (3) एकाधिकारी राष्ट्रवाद व राष्ट्र की उन्नति के नाम पर व्यक्ति का बलिदान
- (4) मार्क्सवादी राष्ट्रवाद वर्गविहीन समाज की स्थापना
- (5) जनवादी राष्ट्रवाद सम्पूर्ण जनता ही वास्तविक राष्ट्र है उसके अधिकारों की रक्षा व हितों का सम्पादन ही सच्चा राष्ट्रवाद है।

राष्ट्रवाद पर विद्वानों के विचार

(1) रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार—“राष्ट्रवाद से अधिक मानववाद को महत्व दिया उन्होंने अन्तराष्ट्रीयवाद का भी समर्थन किया तथा साम्राज्यवाद का विरोध किया।”

(2) श्री अरविन्द घोष के अनुसार—“भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं अपितु ये मेरी मातृशक्ति है और मैं पवित्र राष्ट्र को नमन करता हूँ अर्थात् ये राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे और इसे आध्यात्मिक शक्ति कहते थे।”

राष्ट्रवाद की अवधारणा द्वारा संवर्धित मूल्य

- (1) मानवीय समूह को एक इकाई में गठित करके एक सामूहिक शक्ति प्रदान करना।
- (2) साम्राज्यवाद का विरोध करके निम्न स्तर के समूहों को शोषण से बचाना।
- (3) अनेक जातियों, वर्गों, धर्मों तथा भाषायी समूहों और संस्कृति वाले लोगों को एक स्थान पर भाईचारे के साथ रहना सीखाना।
- (4) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा राष्ट्रवाद का प्राण तत्व होना।
- (5) शासन व्यवस्था, राजनेताओं और किसी एक विचारधारा के स्थान पर राष्ट्र को प्रमुखता प्रदान करना।

पाठगत अवधारणाएँ

- (1) उदारवाद—ऐसी विचारधारा जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अधिक महत्व दिया जाता है।
- (2) साम्राज्यवाद—अपने राष्ट्र की सीमाओं का विस्तार करके अधिक से अधिक राष्ट्रों के अपने अधीन करने का प्रयास
- (3) स्वायत्ता— स्वतन्त्रता
- (4) आकांक्षाओं—इच्छाएँ

अपेक्षित प्रश्न

एक अंकीय प्रश्न

- (1) राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति को समझाइए।
- (2) राष्ट्रवाद का कोई एक सिद्धान्त लिखिए।
- (3) किसी एक विद्वान द्वारा दी गयी राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखिए।

दो अंकीय प्रश्न

- (1) राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने वाले दो कारक लिखिए।
- (2) अलग राष्ट्र की माँग करने वाले किन्हीं चार वैश्विक समूहों का नाम लिखिए।

पाठ-2

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

परिचय

भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी एक लम्बे व कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 ई. को हासिल हुई। ब्रिटिश इण्डिया को दो नए स्वतंत्र देशों भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया गया। पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त को मनाता है वहीं दूसरी ओर भारत अपना स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। यह विभाजन मुस्लिम लीग व उनके नेता जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू बने वहीं पाकिस्तान के राष्ट्र-नायक मुहम्मद अली जिन्ना बने। भारत को राजनैतिक आज़ादी तो प्राप्त हो गई है, मगर आर्थिक व सामाजिक आज़ादी प्राप्त करने में एक लम्बा समय लगा।

इस पाठ में हम निम्नलिखित बिन्दुओं की चर्चा करेंगे जैसे—

- विभाजन के कारण उत्पन्न संकट व समस्याएँ।
- राष्ट्र-निर्माण के सामने आई चुनौतियाँ।
- लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर भारत को स्थापित करने की चुनौती।
- राज्यों का पुनर्गठन करने आई में चुनौतियाँ।

अधिगम उद्देश्य/परिणाम—

- (1) विद्यार्थी भारत की आज़ादी के दौरान उपस्थित चुनौतियों को समझ सकेंगे।
- (2) भारत के विभाजन की प्रक्रिया को समझेंगे व उससे उपजी समस्याओं को अनुभव कर सकेंगे।
- (3) देशी राजे-रजवाड़ों को भारत में विलय करने तथा उस कठिन कार्य में वल्लभभाई पटेल की भूमिका को जानेंगे।
- (4) राष्ट्र, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी मूलभूत अवधारणाओं से परिचित होंगे।
- (5) राज्यों के पुनर्गठन में पुनर्गठन आयोग की भूमिका का अध्ययन करेंगे।

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

नए राष्ट्र की चुनौतियाँ

भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी एक लम्बे व कठिन संघर्ष के बाद 14-15 अगस्त 1947 ई. को हासिल हुई। ब्रिटिश इण्डिया को दो

नए स्वतंत्र देशों भारत व पाकिस्तान के बीच बाँट दिया गया।

‘वर्षों पहले हमने भाग्यवधू से एक प्रतिज्ञा की थी और अब वह समय आ रहा है जब हम उस प्रतिज्ञा को समग्र रूप में या पूरी तौर पर न सही, काफी दूर तक पूरा करेंगे। रात के बारह बजे जबकि दुनिया नींद की गोद में होती है, भारत नये जीवन और स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा।’

— ये वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहे थे। जिसे ‘ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी’ या ‘भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट’ के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के समय दो मुद्दों पर आम सहमति थी।

(1) लोकतांत्रिक सरकार हो।

(2) सरकार सभी की भलाई के लिए काम करें। जिसका लाभ गरीब, कमजोर और सबसे पिछड़े वर्ग को अवश्य हो।

तीन चुनौतियाँ

आज़ादी के समय भारत के सामने निम्नलिखित तीन प्रमुख चुनौतियाँ थी—

(1) राष्ट्र के एकीकरण की समस्या या 565 देशी राजे-रजवाड़ों को भारत में मिलाना—भारत को एकता के सूत्र में बाँधना तथा एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर भारत को गठित करना था जिसमें विविधता, व क्षेत्रीय पहचान का सम्मान हो। लगभग 565 देशी राजे-रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय करना एक कठिन व जटिल चुनौती थी।

(2) लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना—

2.1 सभी नागरिकों को संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारन्टी दी गई।

2.2 सार्वभौमिक मतदान का अधिकार दिया गया अर्थात् प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग व अन्य किसी आधार के भेदभाव के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से समान रूप से मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।

2.3 भारत ने संसदीय शासन पर आधारित, प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया।

3. तीव्र गति से आर्थिक विकास करना—

3.1 भारत को तीव्र गति से आर्थिक विकास करना था। मगर समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ प्राप्त हो।

3.2 सामाजिक रूप से वंचित वर्गों जैसे—गरीब व पिछड़े वर्गों को इसका लाभ अवश्य प्राप्त हो।

3.3 धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

3.4 इसके अलावा भारत के सम्मुख कुछ और समस्याएँ भी थी। जैसे—छुआछूत, साम्प्रदायिक दंगे, जातिवाद, गरीबी, कर्ज के निपटारे की समस्या, आर्थिक असमानता, लोकतंत्र को कायम करना, कृषि का पिछड़ापन, सम्पदा व वस्तुओं के बंटवारे जैसी समस्याएँ व्याप्त थी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया।

लेखक जिन्होंने भारत विभाजन के बारे में लिखा—

साहित्यकारों ने कहानियों, कविताओं, उपन्यासों के माध्यम से विभाजन के समय का मार्मिक चित्रण पेश किया। उन्होंने विस्थापन, हिंसा, साम्प्रदायिक दंगों जैसी समस्याओं तथा लोगों के जीवन पर इनके कारण पड़े प्रभावों का जीवन्त चित्रण पेश किया। उदाहरणतः—

(1) फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी लेखक थे जिन्होंने ‘सुबह-ए-आज़ादी’ नामक कविता लिखी।

(2) अमृता प्रीतम ने कविता ‘वारिस शाह से!’ लिखी।

(3) भीष्म साहनी ने ‘तमस’ नामक उपन्यास की रचना की।

(4) ‘गर्म हवा’ व ‘गदर-एक प्रेम कथा’ विभाजन के समय पर आधारित फिल्में हैं।

विभाजन : विस्थापन और पुनर्वास

14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इण्डिया को भारत तथा पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर दिया गया। विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट न होने के कारण 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि तक भी लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में हैं या पाकिस्तान में।

द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि ‘हिन्दू’ और ‘मुसलमान’ नाम की दो कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग व उनके नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की माँग की। यह सिद्धान्त ही 1947 ई. में ब्रिटिश

इण्डिया को दो देशों में बाँटने का आधार बना।

विभाजन की प्रक्रिया—

ब्रिटिश इण्डिया—ब्रिटिश इण्डिया दो हिस्सों के रूप में था।

(1) ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रान्त जिन पर अंग्रेजों का सीधा नियन्त्रण था।

(2) रजवाड़े जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता या सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। तथा यह घरेलू मामलों में स्वतंत्र थे।

ब्रिटिश इण्डिया

1. भारत

2. पाकिस्तान

पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान

(1947-1971 तक) वर्तमान पाकिस्तान

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के

बाद यह 'बांग्लादेश' नाम

से एक स्वतंत्र देश बना।

3. 565 देशी रियासतें (तीन विकल्प)

1. भारत में शामिल हो जाए।

2. पाकिस्तान में शामिल हो जाए।

3. अपना अलग स्वतंत्र देश बना ले।

1. ब्रिटिश इण्डिया को दो नए स्वतंत्र देशों भारत व पाकिस्तान के बीच बाँट दिया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया। जिन इलाकों में मुसलमान अधिक संख्या में थे, उसे पाकिस्तान को दिया गया तथा बाकि बचे क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया। इस प्रकार पाकिस्तान दो भौगोलिक क्षेत्रों पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। इन दोनों के बीच भारत का एक विशाल क्षेत्र था।

2. खान अब्दुल गफ्फार खान ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त' के आधार पर किए गए विभाजन को गलत माना।

3. बंगाल तथा पंजाब का विभाजन दोनों देशों के बीच हुआ, मगर आज़ादी के दिन तक भी लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में।

4. अल्पसंख्यक—दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की भारी संख्या थी। जैसे पाकिस्तान में कई इलाकों में हिन्दू व सिक्ख आबादी काफी थी। दिल्ली के आस-पास के इलाके में मुसलिमों की संख्या अधिक थी। उन्हें अपने भविष्य को लेकर खतरा महसूस होने लगा। वह अपने ही लोगों के बीच विदेशी बन गए तथा उनमें से बहुतों को अपना घर, व्यापार, सामान, जमीन व जड़ों को छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा।

विभाजन के परिणाम—

1. स्थानांतरण—आज़ादी के समय लोगों को आकस्मिक व अनियोजित तरीके से स्थानांतरित होना पड़ा। यह इतिहास के सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था।

2. लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था बेघर और बेठिकाना होकर महीनों और कभी-कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में अभाव व मजबूरी की ज़िंदगी गुज़रना था। शरणार्थियों का पुनर्वास करना तथा उनके जीवन को मुख्यधारा में लाना भी सरकार के लिए एक विकट समस्या थी।

3. विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर को सीमा पार जाना पड़ा।

4. 5 से 10 लाख लोगों को हिंसक घटनाओं में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।

5. स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में बहुत से बच्चे अपने माता-पिता से बिछुड़ गये।

6. हजारों महिलाओं को अगवा किया गया तथा अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया। कुछ परिवारों ने अपने कुल की मान-मर्यादा को कायम रखने के नाम पर खुद ही अपनी बहू-बेटियों को मार डाला।
7. सामानों और सम्पत्ति का भी बँटवारा हुआ जैसे-टेबुल, कुर्सी, टाईपराटर आदि का भी बँटवारा हुआ।
8. धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे-मुसलमान, सिक्ख, ईसाई के साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के मुद्दे पर अधिकांश नेता सहमत थे।

मेहमाननवाजी में कसर— दंगाइयों ने ट्रेनों को रोककर विरोधी धर्म के लोगों की हत्या कर दी। तथा अन्य लोगों को हलवा, दूध तथा फल खाने के लिए दिए तथा यह कहा कि हमें आपके आने की सूचना समय पर न मिल सकी इसलिए हम आपका स्वागत सही ढंग से नहीं कर सके।

महात्मा गाँधी की शहादत

शान्ति के अग्रदूत, अहिंसा प्रेमी, धार्मिक सद्भाव का संदेश देने वाले महात्मा गाँधी जी ने इस विषम माहौल में दोनों कौमों के बीच में शान्ति व सद्भाव कायम करने का भरसक प्रयास किया। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा गाँधी जी की हत्या के बाद अचानक साम्प्रदायिकता व हिंसा में भारी कमी देखी गई।

रजवाड़ों का विलय

रजवाड़े वह शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता या सर्वोच्च सत्ता संधियों के रूप स्वीकार कर ली थी। तथा उनके बाहरी व विदेश मामलों को अंग्रेज देखते थे तथा वह अपने राज्य के घरेलू व आन्तरिक मामलों को देखने के लिए स्वतंत्र थे। आज़ादी के बाद उनका भाग्य अंग्रेजों ने उनके हाथ ही छोड़ दिया। वह चाहे तो स्वतंत्र रह सकते थे या दोनों देशों में से किसी एक देश में विलय कर सकते थे।

समस्या

भारत के आज़ादी के बाद लगभग 565 देशी राजे-रजवाड़ों का भारत में विलय करना एक बड़ी समस्या थी। जहाँ एक ओर भारत ने शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा था वही दूसरी ओर रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए भी तैयार नहीं थे। देशी रजवाड़ों को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए?, यह एक विकट समस्या थी जिसका भारत को एक नवउदित लोकतांत्रिक देश के तौर पर सामना करना पड़ रहा था। भारत की एकता, अखण्डता व सुरक्षा को कायम रखने के लिए तथा भारत को एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर सफल बनाने के लिए इन छोटे-बड़े सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना आवश्यक था।

1. अधिकांश रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे।
2. भारत सरकार का रुख लचीला था वह कुछ रजवाड़ों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थे जैसे -जम्मू-कश्मीर।
3. भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र पर देशी राजे-रजवाड़ों द्वारा हस्ताक्षर किया गया इस सहमति पत्र को ही 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' के नाम से जाना जाता है।

देशी राजे-रजवाड़ों जिन्हें भारतीय संघ में विलय करना अन्य रियासतों की तुलना में कठिन साबित हुआ। उनमें 1. हैदराबाद 2. मणिपुर 3. जम्मू-कश्मीर 4. जूनागढ़ प्रमुख थे।

हैदराबाद

हैदराबाद, भारत के आज़ादी के समय एक बहुत बड़ी रियासत थी। इसके शासक को 'निज़ाम' के नाम से पुकारा जाता था। तेलंगाना के किसानों ने निज़ाम के खिलाफ आन्दोलन कर दिया। निज़ाम ने विरोध को दबाने के लिए रज़ाकार नामक अर्धसैनिक बल को भेजा जिसने लूटपाट, हत्या व बलात्कार जैसे अनैतिक कार्य करने प्रारम्भ कर दिए। मजबूरन भारतीय सेना को सितंबर 1948 में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके कारण निज़ाम की सेना ने पराजय स्वीकार कर ली तथा आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात् हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया।

मणिपुर

मणिपुर के महाराजा बोधचन्द्र सिंह ने जनमत के दबाव में जून 1948 में चुनाव करवाए इस प्रकार मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर, भारत का पहला क्षेत्र था जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत चुनाव हुआ। भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे